C M Y K

www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 229 नागपुर, शनिवार, 15 जुलाई 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

महाराष्ट्र में मानसून सक्रिय, किसानों को राहत

मुंबई

दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण महाराष्ट्र के सभी भागों में लगातार बारिश हो रही है। जिसके बाद किसानों को काफी राहत मिली है। राज्य के मध्य भाग में अच्छी मात्रा में फसल उत्पादन होता है और इस क्षेत्र में हो रही अच्छी बारिश ने किसानों के साथ-साथ राज्य प्रशासन को भी काफी राहत पहुंचाई है।

पहली बार जुलाई के महीने में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने राज्य के सभी भागों में अच्छी बारिश कराई है। जुलाई के पहले दिन ही राज्य में मानसून प्रवेश कर गया था लेकिन बारिश की गति धीमी थी, लेकिन अब अच्छी खबर है कि पूरे राज्य में बारिश हो रही है। आईएमडी के अधिकारी ने बताया।

उन्होंने कहा कि यह किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगा क्योंकि राज्य काफी दिनों से कृषिक्षेत्र में चुनौती का सामना कर रहा था। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री पांडुरंग निधकर ने कहा कि 'कुल क्षेत्रफल के 66 प्रतिशत हिस्से में खरीफ सीजन के दौरान बोआई की गई है। बारिश में देरी के कारण राज्य प्रशासन थोड़ा चिंतित था, जिसके कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुवाई को स्थगित करने के लिए एक सलाह जारी कर दी थी।

उन्होंने कहा कि अब हम थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं। नासिक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सूखे के बाद हुई जमकर बारिश के कारण शहर और अन्य हिस्सों के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। एक आधिकारी ने बताया, गोदावरी नदी का जलस्तर कल रात से बढ़ गया है।

मौसम विभाग का अनुमान गलत निकला तो किसानों ने दर्ज करा दी एफआइआर

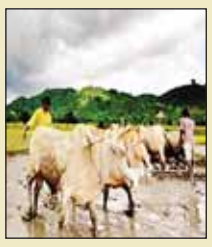

मुंबई

मानसून और बारिश को लेकर मौसम विभाग का अनुमान कभी भी सौ फीसद सटीक साबित नहीं हो पाता। इसके लिए उसे तकरीबन सभी की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बात मामला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया।

मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों ने मौसम विभाग के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। आरोप है कि बीज कंपनियों से मिलीभगत कर विभाग ने उन्हें गलत जानकारी दी। किसानों ने उनकी बात पर भरोसा करके खेतों में बिजाई कर दी, लेकिन महकमे के अनुमान के उलट जून में बारिश बेहद कमजोर रही। नतीजतन किसानों को लाखों रुपये की चपत लग गई। बीड जिले की मजलगांव पुलिस का कहना है कि अभी केस दर्ज नहीं किया गया है। शिकायत की जांच की जा रही है।

शिकायतकर्ताओं में से एक आनंदगांव निवासी किसान गंगाभिषण थवरे का कहना है कि पुणे व कोलाबा स्थित मौसम विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर गलत सूचना किसानों को दी। उनका कहना है कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। किसान बादलों की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। मौसम विभाग ने कहा था कि जून में बेहतरीन बारिश होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की गई है कि वह मामले में दखल देकर कार्रवाई करें।

यूपी असेंबली में विस्फोटक

गुस्साये योगी आदित्यनाथ बोले- साजिश का पर्दाफाश होना जरूरी

लखनऊ

यूपी विधानसभा के अंदर 12 जुलाई को मिला सफेद पाउडर विस्फोटक है। एंटी माइनिंग और डॉग स्क्वॉड की टीम जब विधानसभा के अंदर जांच कर रही थी तो इसी दौरान उन्हें सफेद पाउडर मिला था। इस पाउडर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। जांच में पता चला है कि यह पाउडर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है, लेकिन यह डेटोनेटर के साथ ही काम करता है, इससे अलग से विस्फोट नहीं होता। यह विस्फोटक यह उसी जगह पर रखा था, जहां तमाम पार्टियों के नेता बैठते हैं। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाईलेवल मीटिंग बुलाई थी। यह विपक्ष वाली लाइन में मिला था।

यूपी विधानसभा में मिला पाउडर निकला विस्फोटक

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 150 ग्राम पाउडर मिला है। यह एक पुड़िया में मिला। विस्फोटक मिलना चिंताजनक है। यह एक खतरनाक साजिश का हिस्सा है। जो इस साजिश के पीछे हैं उनका पर्दाफाश होना जरूरी है। मैं विपक्षी दलों से इस मामले में सहयोग की अपील करता हूं।

उन्होंने इसकी जांच से करवाने की मांग की। कुछ लोग शरारत पर उतर आए हैं, उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। योगी ने कहा कि विधानसभा के भीतर बिना पास की एंट्री बंद होनी चाहिए। सदन के सभी सदस्य सुरक्षा संबंधी गाइडलाइंस को फॉलो करें। सीएम योगी ने यह भी कहा कि हमें विधानसभा की सुरक्षा के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। सीएम ने कहा कि सुरक्षा के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं होती, इसके लिए आपसी सहमति भी जरूरी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक- इस विस्फोट का नाम बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह विस्फोटक अंदर कैसे पहुंचा। दरअसल, यूपी विधानसभा में एंट्री के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा चक्रों से गुजरना पड़ता है।

यही नहीं विधानसभा में सिर्फ विधायकों, मंत्रियों, सफाईकर्मचारी और मार्शल को ही जाने की इजाजत है। इसे लेकर कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि यह राज्य की सुरक्षा का सच सामने लाता है। विधानसभा में विस्फोटक मिलना हैरानी की बात है। ये लोग जब विधानसभा को सुरक्षित नहीं कर सकते तो जनता को क्या करेंगे।

यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षाकर्मी अपना काम कर रहे हैं, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आतंकी पूरे भारत में पांव पसारने में लगे हैं, लेकिन यूपी में जगह नहीं मिलेगी।

समाजवादी पार्टी के नेता राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि ये तो बहुत ख़तरनाक स्थिति है, सघन जांच की ज़रूरत है। जनता के बीच में तत्काल रिपोर्ट आनी चाहिए।

विधानसभा में ये हाल है तो बाकी यूपी की सुरक्षा का अंदाजा लगा सकते हैं। बीएसपी के असलम रायनी ने कहा कि 403 विधायकों की जिंदगी कोहिनूर हीरे की तरह है।

चीन के साथ सीमा विवाद पर सरकार को मिला विपक्ष का साथ

नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान और सिक्किम के डोकलाम में चीन के साथ टकराव से पैदा हुए हालात को लेकर शुक्रवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई इस बैठक में तमाम दलों के नेता मौजूद रहे। राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें चीन से गतिरोध व कश्मीर के हालात की जानकारी दी। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए यह कदम उठाया है। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि विदेश मंत्री और विदेश सचिव ने सीमा विवाद खासकर डोकलाम मसले पर विपक्ष को विस्तृत जानकारी दी है। सभी दलों ने सरकार को समर्थन का भरोसा दिया है।

वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले है। हमने सरकार को हालात से निपटने के लिए कूटनीति के इस्तेमाल की सलाह दी।

संसद सत्र से पहले सरकार सबसे बड़े पड़ोसी देश व कश्मीर मसले से निपटने की सर्वसम्मत रणनीति बनाना चाहती है। चीन के साथ ताजा विवाद सिक्किम के डोकलाम में भारत, चीन व भूटान के ट्राईजंक्शन की स्थिति में चीन द्वारा बदलाव से पैदा हुआ है। चीन वहां सड़क बनाना चाहता है।

तीन हफ्ते से वहां दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ है। वहीं जम्मू-कश्मीर में सोमवार को आतंकियों ने सात अमरनाथ यात्रियों की हत्या कर दी है। सरकार इसके बाद उत्पन्न हालात व सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी विपक्ष को देना चाहती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दोनों मामलों को लेकर लगातार पीएम मोदी व सरकार पर निशाना साध रहे हैं।

नोटबंदी व जीएसटी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

उधर 18 विपक्षी दलों ने 17 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान नोटबंदी, जीएसटी व अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई बैठक में इन दलों ने संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर विचार किया था।

हाल ही में बिगड़े हैं रिश्ते

गौरतलब है कि डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल है। इस दौरान चीन की तरफ से लगातार उकसावे वाले बयान आ रहे हैं। इससे पहले चीन के एक सरकारी अखबार के संपादकीय में सीधे-सीधे धमकी देते हुए लिखा गया था कि इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाएं और भारत को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ें वो डोकलाम से अपने सैनिक हटा ले। अखबार लिखता है कि बीजिंग अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता के मामले में किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं चीनी सरकार के मुख्यपत्र माने जाने पीपुल्स डेली ने भी मंगलवार को अपने संपादकीय पन्ने पर 22 सितंबर 1962 में छपे एक भड़काऊ संपादकीय को दोबारा प्रकाशित किया है। इस लेख में उसने क्षेत्रीय उकसावे को लेकर भारत को चेतावनी दी है। भारत, चीन और भूटान सीमा पर स्थित डोकलाम पर चीन अपना दावा कर रहा है, वहीं भारत और भूटान का कहना है कि ये हिस्सा भूटान का है और विवादित है।

कश्मीर में भी दखल दे रहा चीन

चीनी विदेश मंत्रालय ने कश्मीर मुद्दे को अपना मोहरा बनाते हुए कहा कि वहां के हालात ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेंग शुआंग ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के अहम देश हैं। कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास टकराव जारी है। इससे ना दोनों देशों बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता को नुकसान है।

सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या सरकार खोल सकती है बोफोर्स केस

नई दिल्ली

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने कहा है कि वह बोफोर्स का मामला तभी खोल सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार उसे इसका आदेश दे। इससे पहले गुरुवार को संसदीय समिति ने बोफोर्स मामले की जांच फिर से कराने का सुझाव दिया था। समिति का कहना था कि पिछली जांच में कई कमियों को देखते हुए यह मामला फिर से खोला जाना चाहिए।

संसदीय समिति के सुझाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीबीआइ के प्रवक्ता आरके गौर ने कहा कि हमें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार के आदेश की जरूरत होगी। कोई संसदीय समिति हमें जांच फिर से शुरू करने के लिए नहीं कह सकती। इससे ज्यादा इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते हैं।लोक लेखा समिति से संबद्ध रक्षा मामलों की उप समिति ने बोफोर्स जांच फिर से कराने का सुझाव दिया है।

संघ प्रमुख मोहन भागवत जम्मू पहुंचे, आतंकवाद पर बनेगी रणनीति

जम्मू

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय बैठक में विचार परिवार की राजनीति तय करने के लिए संघ प्रमुख डा. मोहन भागवत शुक्रवार सुबह जम्मू पहुंच गए। रेल मार्ग से सुबह छह बजे जम्मू पहुंचे आरएसएस के सर संघ चालक डा.मोहन भागवत सीधे बैठकों के लिए वेद मंदिर रवाना हो गए। उनके साथ संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी भी थे।

संघ की राष्ट्रीय बैठक जम्मू में सत्रह से उन्नीस जुलाई तक चलेगी, इससे पहले व बाद में भी संघ प्रमुख बैठकें करेंगे। यह सिलसिला बाईस जुलाई तक जारी रहेगा। राज्य में पहली बार हो रही इस बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों से 40 राज्य प्रचारकों समेत 200 के करीब प्रचारक हिस्सा लेंगे।

राज्य में श्री बाबा अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी हमले के चलते

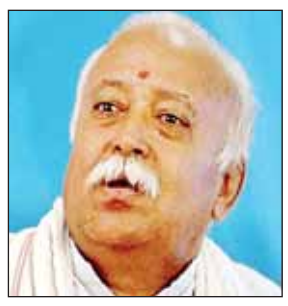

संघ की राष्ट्रीय बैठक में आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा, कश्मीर के हालात पर मंथन तय है। राष्ट्रीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए राज्य प्रचारकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है।

श्री बाबा अमरनाथ यात्रा पर कश्मीर में हमले से उपजे हालात का असर देश की राजनीति पर पड़ रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय बैठक में अमरनाथ यात्रा का विरोध करने वालों को भी कड़ा संदेश दिया जाएगा।

नौ दिन तक बैठक वेद मंदिर के अंदर होगी। इसमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और विहिप के राष्ट्रीय नेता भी हिस्सा लेंगे। इसमें देश के समक्ष चुनौतियों पर भी मंथन होगा। 22 जुलाई तक चलने वाली इस राष्ट्रीय बैठक के माध्यम से देश विरोधी तत्वों को संदेश दिया जाएगा कि उनका सख्ती से सामना होगा।

18 से 20 जुलाई के बीच भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव भी इसमें हिस्सा लेंगे। बैठक में कश्मीर के हालात पर मंथन के दौरान वहां सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ साजिशों व पाकिस्तान के एजेंडे को प्रभावी बनाने की अलगाववादियों व पत्थरबाजों की कोशिशों पर भी चर्चा होगा।

इसके साथ ही यह भी तय होगा कि राज्य में विरोधी तत्वों का मुकाबला कैसे किया जाए। इस दौरान प्रांत प्रचारकों के कार्यो और गतिविधियों का लेखाजोखा प्रस्तुत करने के साथ कार्ययोजना का मसौदा भी तैयार होगा।

कश्मीर में भड़की हिंसा, 12 से अधिक लोग हिरासत में

श्रीनगर

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा और उत्तरी कश्मीर के सोपोर में शुक्रवार को हिंसक झड़पों में आठ लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। जनजीवन भी प्रभावित रहा। ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में लगातार चौथे शुक्रवार को भी नमाज-ए-जुमे की अजान नहीं गूंजी। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक, कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी, शब्बीर शाह, नईम अहमद खान, हिलाल वार को प्रशासन ने उनके घरों में ही नजरबंद रखा।

हुर्रियत कांफ्रेंस ने पूरे कश्मीर में मस्जिदों के बाहर राष्ट्रविरोधी प्रदर्शनों का आह्वान किया था। गत दिनों बडगाम में मारे गए तीन आतंकियों की मौत के बाद से तनाव बना हुआ है। प्रशासन ने श्रीनगर के छह थाना क्षेत्रों के अलावा शोपियां, पुलवामा, त्राल और बडगाम के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लगा रखी थी। श्रीनगर के डाउन-टाउन में सामान्य जनजीवन ठप रहा। लालचौक, राजबाग, बटमालू, बेमिना, जवाहरनगर, डलगेट, सोनवार समेत श्रीनगर के किसी अन्य हिस्से पर नहीं पड़ा। बारामुला, बांडीपोर, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, बडगाम, गांदरबल, कंगन, काजीगुंड, पहलगाम, बिजबिहाड़ा, पांपोर व अवंतीपोरा में सामान्य जनजीवन पर प्रशासनिक पाबंदियों या अलगाववादियों के प्रदर्शनों के आह्वान का असर नहीं दिखा। अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, त्राल, सोपोर, पल्हालन में जनजीवन प्रभावित रहा। सबसे ज्यादा हिंसक झड़पें अनंतनाग और चटपोरा व पुलवामा में हुई। पुलिस ने किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं की है। सूत्रों ने बताया कि आठ लोग जख्मी हैं। पुलिस ने अनंतनाग में 15, पुलवामा में दो और सोपोर में दो युवकों को पथराव के दौरान पकड़ा है।

अब डेंगू नहीं बनेगा महामारी, इस छोटे से टेस्ट से घर में ही चलेगा बीमारी का पता

नई दिल्ली

मानसून के दस्तक देने के साथ ही मच्छरों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है। हर शख्स खौफ के साथ जी रहा होता है कि न जाने कब और कहां वो मच्छरों का शिकार बन जाएगा। आमतौर पर डेंगू और चिकनगुनिया पहले किसी खास इलाके तक सीमित रहता था। लेकिन अब इनका फैलाव देश के अलग-अलग हिस्सों में भी हो रहा है। मच्छरों से लड़ने के लिए दवा के छिड़काव जैसे पारंपरिक तरीके नाकाफी साबित हो रहे हैं। अब डेंगू, जीका और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के खात्मे के लिए रोबोटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग का सहारा लिया जा रहा है। इस क्रम में दिग्गज आइटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल की डिजीज टेक्नॉलाजी कंपनी वेरिली लाइफ साइंसेज से साझेदारी की है।

मच्छरों की मार

17 फीसद संक्रामक बीमारियों में मच्छरजनित रोगों की हिस्सेदारी। मच्छरजनित बीमारियों से सालाना 10 लाख मौत। 100 देशों में डेंगू के साये में 2.5 अरब आबादी रहती है। मलेरिया से 4 लाख लोगों की सालाना मौत ।

बायोसेंसर से डेंगू पर लगाम

डेंगू से होने वाली ज्यादातर मौतों के पीछे सबसे बड़ी वजह यह होती है कि इस बीमारी का समय पर पता नहीं लग पाता, लेकिन अब सिर्फ 20 मिनट में डेंगू का पता लगाया जा सकेगा। इसके लिए एमिटी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ. जागृति नारंग ने बायोसेंसर नाम की विशेष मेडिकल डिवाइस तैयार की है।

बायोसेंसर की खासियत यह है कि यह सभी प्रकार के डेंगू का पता लगा लेगा। अभी तक डॉक्टर डेंगू का पता लगाने के लिए या तो मरीज की एंटी बॉडीज जांच करते हैं या फिर डेंगू का प्रकार (स्ट्रेन टेस्ट) पता लगाने के लिए अलग-अलग जांच की जाती है।

स्ट्रेन टेस्ट में सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर किसी व्यक्ति को टाइप वन का डेंगू है और उसकी टाइप टू की जांच करा ली गई तो रिपोर्ट निगेटिव (फाल्स) आएगी। ऐसे में मरीज की जान को खतरा भी हो सकता है।

ऐसे आया आइडिया

एमिटी में नैनो टेक्नोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉ. जागृति नारंग बताती हैं कि करीब दो साल पहले वह अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गई थीं।

वहां सैकड़ों डेंगू के मरीज थे और जांच के लिए लाइन लगी थी। उसके बाद उनके दिमाग में डेंगू की जांच के लिए आसान और सस्ती डिवाइस तैयार करने का आइडिया आया। फिर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के डॉ. सीएस पुंडीर और विवि की छात्र चेताली सिंघल के साथ इस पर काम शुरू किया।

नारंग कहती हैं कि दो साल के शोध और करीब चार लाख रुपये खर्च करने के बाद हम बायोसेंसर तैयार कर पाए। अब इसे पेटेंट के लिए भेजा गया है। शोध पत्र में भी यह प्रकाशित हो चुका है।

बायोसेंसर ऐसे काम करेगा

बायोसेंसर में एक इलेक्ट्रोड पर डेंगू का कॉमन डीएनए लगा है। अभी किसी व्यक्ति के डीएनए को इस इलेक्ट्रोड पर रखेंगे तो वह बता देगा कि व्यक्ति को डेंगू है या नहीं। डॉ. जागृति नारंग कहती हैं कि अभी हम बायोसेंसर को और विकसित कर रहे हैं, ताकि डीएनए की जगह इसमें सिर्फ रक्त रखकर डेंगू का पता लगाया जा सके। इसमें करीब एक साल और लगेगा। वह कहती हैं कि प्रोटोटाइप में ज्यादा पैसा खर्च हुआ, लेकिन बड़ी संख्या में उत्पादन में एक बायोसेंसर करीब सौ रुपये का पड़ेगा और एक डिवाइस से 10 से ज्यादा मरीजों की जांच की जा सकेगी।

डेंगू-चिकनगुनिया के लक्षण

बुखार-तेज बुखार होना, डेंगू-चिकनगुनिया के प्रमुख और शुरुआती लक्षणों में शामिल है। अगर आपको सप्ताह भर से भी अधिक समय तक बुखार बना हुआ है और कम नहीं हो रहा, तो डॉक्टर के पास जाकर जांच अवश्य कराएं।

लैंड मैपिंग में हुई धांधली को लेकर गुजरात सीएम ने दिये जांच के आदेश

अहमदाबाद

गुजरात के सवा करोड़ किसानों की सैटेलाइट के जरिए की गई जमीन पैमाइश में अनियमितता उजागर होने के बाद मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने जिला कलेक्टरों को शिकायतें लेकर उनका तुरंत निपटारा करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस पिछले कुछ समय से इस मुददे को उठा रही थी लेकिन राजस्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह चूडास्मा किसी तरह की गड़बड़ी से इन्कार करते रहे।

मुख्यमंत्री रुपाणी ने सैटेलाइट के जरिए लैंड मैपिंग में ओवरलैपिंग की शिकायतों का जायज बताते हुए जिला कलेक्टरों को आदेश दिया है कि किसान व लोगों की जमीन व संपत्ति संबंधी राजस्व रिकार्ड की शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निपटाएं। रुपाणी ने कहा कि जमीन

की पैमाइश में गड़बड़ी की फरियाद आ रही है जिसे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इसमें सुधार करने को कहा गया है। इससे पहले राजस्व मंत्री चूडास्मा ने कहा था कि सरकार किसी की जमीन नहीं लेना चाहती। जमीन पैमाइश में कोई अनियमितता नहीं हुई है यह उत्तम प्रकार से की गई मापणी है जिसे देखने व समझने के लिए अन्य राज्यों के राजस्व अधिकारी भी गुजरात आ रहे हैं। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढ़वाडिया ने बताया कि जिस प्रकार शर्ट का एक बटन गलत बंद करने से सभी बटन अस्त व्यस्त हो जाते हैं वैसे ही जमीन माप में भी एक चूक समूची मैपिंग को बिगाड़ देती है। सैटेलाइट मैपिंग बंद कमरों में बैठकर कर दी गई। जमीन की माप के लिए हर गांव में कंट्रोल प्वाइंट बनाना होता है लेकिन इस माप में पूरे राज्य में एक भी कंट्रोल प्वाइंट नहीं बनाया गया। इसके साथ ही 9 सीमा चिन्ह बनाकर जमीनों की मैपिंग होती है इसकी भी उपेक्षा कर दी गई। कांग्रेस ने सैटेलाइट जमीन माप की न्यायिक जांच कराने, दोषी एजेंसी व अधिकारियों पर कार्यवाही करने तथा जमीन की फिर से टोटल स्टेशन सर्वे पद्धति से माप की मांग की है। चूंकि इस माप पर 300 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं तथा अब फिर से माप कराने पर एक हजार करोड़ खर्च होंगे।